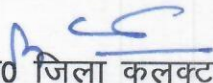


कमांक प 8 (क) नियम/ डीएलबी/8226 जयपुर दिनांक 31.03.2010 की प्रति पेश की गई थी जिसमें नगरपालिका अधिनियम 2009 (अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2009) की धारा 327 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या कमांक प 8 (84) एल.एस.जी. (62) पार्ट 540-784 दिनांक 05.02.1987 को अधिकृत करते हुए राज. सरकार द्वारा धारा 327 में निगरानी सुनने के लिए, प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास विभाग, शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग, निदेशक एवं शासन उप सचिव स्वायत्त शासन विभाग को अधिकृत किया गया है। जिसमें इस धारा में निगरानी सुनने का अधिकार इन्हीं को है। जहा पर वकील निगरानीगुजार/अप्रार्थी का कथन था की निगरानी सुनने का अधिकार राज. सरकार को है। ओर ये सभी अधिकार जिला कलक्टर मे समाहित है। वहा पर इस अधिसूचना के खिलाफ कोई आदेश आदि पेश नहीं कियो गये है। जिससे विदित है कि नगरपालिका अधिनियम की धारा 327 में पट्टे की निगरानी का अधिकार स्वायत्त विभाग के अधिकारी को ही है। जो अपने आप में इस न्यायालय को श्रवणाधिकार नहीं है।

अतः अप्रार्थी/अनिगरानीगुजार नम्बर 1 का प्रार्थनापत्र वॉर्ड वाई लॉ होने पर स्वीकार किया जाता है। तथा निगरानीगुजार द्वारा प्रस्तुत निगरानी उनवानी देवीशरण बनाम लक्ष्मीदेवी मु. नं. 13/17 इसी स्टैज पर खारिज की जाती है। निगरानीगुजार सक्षम न्यायालय में चाराजोई करने में स्वतंत्र रहेगे। निर्णय की प्रति आयुक्त नगरपरिषद हिण्डौन को उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।


अति० जिला कलक्टर
करौली